08/04/2024

शामिल विषय (TOPICS COVERED)

- **व्यापारियों ने यूएई को कम कीमत पर प्याज के निर्यात पर नाराजगी जताई (GS PAPER III: कृषि, बाहरी क्षेत्र)**
- **इस चुनावी मौसम में, एमएसएमई जीएसटी सुधार की मांग वाले उम्मीदवारों का पीछा कर रहे हैं। (GS PAPER III: विनिर्माण क्षेत्र, कराधान)**
- **समावेशी स्वास्थ्य देखभाल के लिए भारत के मार्ग को आकार देना (GS PAPER II: स्वास्थ्य क्षेत्र)**
- **स्वच्छंद हाथी: आरबीआई के दर निर्णय पर (GS PAPER III: मुद्रास्फीति)**
- **गर्मी को मात दें: अधिक लू चलने की आईएमडी की चेतावनी पर (GS PAPER I: प्राकृतिक घटना)**
- **बहुत जल्दी ख़त्म हो गया - भारत में युवा आत्महत्या का विषय (GS PAPER I: समाज)**

व्यापारी संयुक्त अरब अमीरात को कम कीमत पर प्याज के निर्यात से निराश हैं (GS PAPER III: बाहरी क्षेत्र)

- भारत सरकार ने संभावित घरेलू कमी की चिंताओं के कारण प्याज के निर्यात पर विस्तारित प्रतिबंध लगा दिया।
- प्रतिबंध के बावजूद, सरकार ने राजनयिक अनुरोधों के जवाब में संयुक्त अरब अमीरात जैसे बाजारों में कुछ शिपमेंट की अनुमति दी।
- भारतीय किसान और व्यापारी चिंतित हैं क्योंकि इनमें से कुछ स्वीकृत शिपमेंट संयुक्त अरब अमीरात के स्टोरों में बहुत अधिक कीमतों पर बेचे गए थे।
- भारत में किसानों को निर्यात के लिए इच्छित प्याज के लिए कथित तौर पर बहुत कम कीमत, लगभग ₹12 से ₹15 प्रति किलोग्राम का भुगतान किया जा रहा है।
- हालाँकि, यही प्याज संयुक्त अरब अमीरात के स्टोरों में ₹120 प्रति किलोग्राम से अधिक कीमत पर बेचा जा रहा है, जिससे चयनित आयातकों को अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है।
- भारत सरकार ने 3,600 टन की त्रैमासिक सीमा के साथ संयुक्त अरब अमीरात को 14,400 टन प्याज के निर्यात की अनुमति दी। इस कोटा से परे अतिरिक्त निर्यात को मंजूरी दी गई।
- भारत, पाकिस्तान और मिस्र जैसे देशों द्वारा लगाए गए निर्यात प्रतिबंधों के कारण वैश्विक प्याज की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं। संयुक्त अरब अमीरात जैसे प्रमुख बाजारों में कीमतें 1500 डॉलर प्रति टन तक पहुंच गईं।
- कथित तौर पर संयुक्त अरब अमीरात में भारत की हालिया खेप लगभग $500 से $550 प्रति टन पर बेची गई, जो मौजूदा बाजार कीमतों से काफी कम है।

PatriotiCIAS

- संयुक्त अरब अमीरात के आयातकों को भारत से प्याज शिपमेंट के माध्यम से ₹300 करोड़ से अधिक का अनुमानित मुनाफा हुआ है। अतिरिक्त 10,000 टन कोटा के साथ, अतिरिक्त ₹1,000 करोड़ का लाभ होने की उम्मीद है।
- इन निर्यातों का प्रबंधन विशेष रूप से राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल) के माध्यम से किया जाता है, जो सहकारिता मंत्रालय के तहत एक सरकारी स्वामित्व वाली संस्था है।
- निर्यातकों को सूचित किया गया कि निर्यात सरकार-से-सरकार के आधार पर किया जाता है, जिसमें आयातक देश नामांकित आयातकों को कोटा आवंटित करता है। एग्रीबाजार पोर्टल पर ई-टेंडरिंग के माध्यम से खरीद की जाती है।
- यूएई की ओर से, निजी व्यापारी और सुपरमार्केट श्रृंखलाएं, न कि सरकारी एजेंसियां, कथित तौर पर ये शिपमेंट प्राप्त कर रही हैं।
- आमतौर पर, व्यापार सौदों में, आपूर्तिकर्ता सबसे कम कीमत के लिए बोली लगाते हैं, और खरीदारों को उच्चतम प्रस्तावित कीमत के आधार पर चुना जाता है। हालाँकि, निर्यातकों का दावा है कि यहाँ ऐसा नहीं है।
- हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ने निर्यात प्रक्रिया और मूल्य निर्धारण के बारे में चिंता जताई है, यह देखते हुए कि विदेशों में बेची जाने वाली प्याज की कीमतें अंतरराष्ट्रीय कीमतों से कम हैं, जो उस समय लगभग 1,450 डॉलर प्रति टन थीं।
- निर्यात मूल्य निर्धारण प्रक्रिया और निर्यातकों और आयातकों की पहचान के संबंध में वाणिज्य, उपभोक्ता मामले और सहयोग मंत्रालयों द्वारा प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया गया है।
- कृषि मंत्रालय ने कहा कि उसका ध्यान पूरी तरह से फसल अनुमान प्रदान करने पर है और निर्यात कीमतें निर्धारित करने या निर्यातकों और आयातकों की पहचान करने में शामिल नहीं है।

इस चुनावी मौसम में, एमएसएमई जीएसटी सुधार की मांग वाले उम्मीदवारों का पीछा कर रहे हैं (GS PAPER III: विनिर्माण क्षेत्र, कराधान)

- विभिन्न क्षेत्रों में लगभग सात करोड़ इकाइयों के साथ भारत की अर्थव्यवस्था के एक महत्वपूर्ण हिस्से का प्रतिनिधित्व करने वाले एमएसएमई माल और सेवा कर (जीएसटी) दरों में कटौती की मांग कर रहे हैं।
- जीएसटी दरों में कटौती एमएसएमई प्रतिनिधियों की प्राथमिक मांग है क्योंकि देश लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहा है।
- ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरर्स ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय संयोजक और एमएसएमई डेवलपमेंट फोरम के उपाध्यक्ष सुधीर झा एमएसएमई के महत्व पर प्रकाश डालते हैं, क्योंकि लगभग 12 करोड़ लोग इन पर निर्भर हैं।
- कई एमएसएमई जीएसटी स्लैब की जटिलता से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए हैं, जिसने वर्षों से उनके संचालन को पंगु बना दिया है।
- अधिकांश एमएसएमई के पास अपने छोटे पैमाने के संचालन के कारण जीएसटी के संसाधनों और समझ की कमी है, जिससे अनुपालन में चुनौतियाँ आती हैं।
- सूक्ष्म और लघु स्तर की इकाइयां, हालांकि कम टर्नओवर के कारण तकनीकी रूप से जीएसटी से छूट प्राप्त हैं, बड़े जीएसटी-पंजीकृत उद्योगों के आपूर्तिकर्ताओं के रूप में अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होती हैं, जिसके परिणामस्वरूप दस्तावेज़ीकरण आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ होने पर व्यावसायिक अवसरों का नुकसान होता है।

Patriot IAS

- कोयंबटूर और लुधियाना में एमएसएमई समूहों ने चुनाव उम्मीदवारों को अपनी मांगें सौंपी हैं।
- कोयंबटूर में, मुख्य मांग सूक्ष्म और लघु-स्तरीय इकाइयों द्वारा किए जाने वाले श्रम शुल्क पर जीएसटी को मौजूदा 12% से घटाकर 5% या शून्य करना है।
- लुधियाना में, ऑटो कंपोनेंट इकाइयों पर कुछ घटकों पर 28% कर का बोझ है, जो विशिष्ट क्षेत्रों में जीएसटी दर में कटौती की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।

समावेशी स्वास्थ्य देखभाल के लिए भारत के मार्ग को आकार देना (GS PAPER II: स्वास्थ्य क्षेत्र)

भारत के स्वास्थ्य समानता के मुद्दों के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में सुधार से परे हो

- **विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है** स्वास्थ्य समानता पर ध्यान केंद्रित करना, जो वैश्विक स्वास्थ्य और न्याय के लिए महत्वपूर्ण है।
- विश्व **स्वास्थ्य संगठन (WHO) स्वास्थ्य को एक मौलिक मानव अधिकार मानता है और** सभी के लिए स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर देता है।
- इस वर्ष की **थीम है "मेरा स्वास्थ्य, मेरा अधिकार"** स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँचने के लिए व्यक्तियों के अधिकारों पर प्रकाश डालना।
- कोविड-19 महामारी, पर्यावरणीय संकट और बढ़ती सामाजिक-आर्थिक असमानताओं ने स्वास्थ्य देखभाल पहुंच में अंतराल को संबोधित करने की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित किया है।
- **140 से अधिक देशों में स्वास्थ्य को संवैधानिक अधिकार के रूप में मान्यता दिए जाने के बावजूद, दुनिया की आधी से अधिक आबादी को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं तक पूरी पहुंच नहीं है।**
- सभी के लिए स्वास्थ्य के अर्थशास्त्र पर WHO परिषद स्वास्थ्य समानता को बढ़ावा देने के महत्व पर जोर देती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी को स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्राप्त हो।
- विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 स्वास्थ्य समानता प्राप्त करने के लिए आवश्यक चल रहे प्रयासों की याद दिलाता है, जो दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए आशा प्रदान करता है।

स्वास्थ्य समता का अर्थ

- **सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय स्थितियों जैसे कारकों पर विचार करते हुए स्वास्थ्य समानता यह सुनिश्चित करती है कि सभी को अच्छे स्वास्थ्य का समान अवसर मिले।**
- विश्व **स्वास्थ्य संगठन (WHO) का लक्ष्य रोकथाम योग्य स्वास्थ्य असमानताओं को खत्म करना है** विभिन्न सामाजिक और आर्थिक समूहों के बीच।
  - विशिष्ट एजेंसी: WHO संयुक्त राष्ट्र की अग्रणी विशिष्ट एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य को निर्देशित और समन्वयित करने पर केंद्रित है।
  - संविधान (1948): WHO को "सभी लोगों द्वारा स्वास्थ्य के उच्चतम संभावित स्तर की प्राप्ति" हासिल करने के लिए व्यापक आदेश प्रदान करता है।
  - सदस्यता: विश्व स्वास्थ्य सभा (डब्ल्यूएचए) के माध्यम से भाग लेने वाले 194 सदस्य देशों का समावेश
- यह गरीबी, भेदभाव, शिक्षा तक सीमित पहुंच, स्वस्थ भोजन, स्वच्छ पानी और आवास जैसे मूल कारणों को संबोधित करता है।

PatriotiAS

- उदाहरण के लिए, गरीबी में पैदा हुए बच्चे को बुनियादी जरूरतों तक पहुंच नहीं होती है, जिससे दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याएं पैदा होती हैं।
- **महामारी और जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक चुनौतियाँ स्वास्थ्य संबंधी असमानताओं को बढ़ाती हैं** , जिससे हाशिए पर रहने वाले समूह सबसे अधिक प्रभावित होते हैं।
- भारत में, विविध आबादी को स्वास्थ्य देखभाल संबंधी असमानताओं का सामना करना पड़ता है, ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी पहुंच सीमित है।
- स्वास्थ्य समानता हासिल करने के लिए कानून से परे प्रयासों की आवश्यकता है, जिसमें सरकारें, समुदाय और व्यक्ति शामिल हों।
- चुनौतियों में सामाजिक अन्याय, वैश्विक स्वास्थ्य मुद्दे और स्वास्थ्य देखभाल पहुंच को बाधित करने वाले संघर्षों को संबोधित करना शामिल है।
- कोविड -19 महामारी और जलवायु परिवर्तन ने स्वास्थ्य समानता के अंतर को बढ़ा दिया है, जिससे हाशिए पर रहने वाले समुदाय सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं, जबकि संघर्ष स्वास्थ्य देखभाल प्रावधान में बाधा डालते हैं।

भारत की स्वास्थ्य समानता चुनौती

- स्वास्थ्य देखभाल परिणामों और पहुंच में अंतर के कारण, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, भारत को स्वास्थ्य समानता हासिल करने में लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
- शहरी मलिन बस्तियाँ, जिनमें 17% से अधिक महानगरीय क्षेत्र शामिल हैं , भीड़भाड़, खराब स्वच्छता और स्वच्छ पानी तक सीमित पहुंच के कारण गंभीर स्वास्थ्य असमानताओं से पीड़ित हैं ।
- भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अनुसार, तपेदिक जैसी संक्रामक बीमारियाँ गैर-झुग्गी बस्तियों की तुलना में मलिन बस्तियों में 1.5 गुना अधिक आम हैं।
- जाति और लिंग में असमानताएं महत्वपूर्ण हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में बाल मृत्यु दर अधिक है और टीकाकरण दर कम है।
- सबसे कम संपत्ति वर्ग में महिलाओं में एनीमिया की व्यापकता 59% है, जो उच्चतम वर्ग से दोगुना है, जो स्वास्थ्य परिणामों पर जाति, लिंग और आर्थिक स्थिति के प्रभाव को दर्शाता है।
- गैर-संचारी रोग (एनसीडी) 60% से अधिक का योगदान करते हैं पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अनुसार , 2030 तक अनुमानित आर्थिक लागत 6 ट्रिलियन डॉलर से अधिक होने के साथ, भारत में होने वाली सभी मौतों की संख्या।
- डॉक्टरों की भारी कमी है, प्रति 1,000 लोगों पर केवल 0.8 डॉक्टर हैं, जो अनुशंसित अनुपात से कम है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह कमी विशेष रूप से गंभीर है।
- स्वास्थ्य समानता हासिल करने के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के अलावा स्वास्थ्य के व्यापक सामाजिक-आर्थिक निर्धारकों पर ध्यान देने की आवश्यकता है।
- सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज को आगे बढ़ाने और भारत के लिए अधिक न्यायसंगत भविष्य बनाने के लिए सरकार, नागरिक समाज, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और समुदायों के बीच सहयोग से युक्त एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है।
- सरकारें फंडिंग, नीतियों और कानूनों के माध्यम से स्वास्थ्य देखभाल को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं , जैसे कि भारत की आयुष्मान भारत पहल आर्थिक रूप से निचले 40% लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करती है।

PatriotIAS

- एनआरएचएम और एनयूएचएम सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) का लक्ष्य ग्रामीण और शहरी के बीच स्वास्थ्य देखभाल संबंधी असमानताओं को कम करना है । भारत पहुंच का विस्तार करके, बुनियादी ढांचे को मजबूत करके और कमजोर आबादी को आवश्यक सेवाएं प्रदान करके।
- स्वास्थ्य समानता प्राप्त करने के लिए स्वास्थ्य साक्षरता महत्वपूर्ण है, और NHM में स्वास्थ्य शिक्षा को एकीकृत करने से लोगों को न्यायसंगत देखभाल प्राप्त करने और सूचित स्वास्थ्य निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाया जा सकता है।
- सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र, निवारक शिक्षा, कार्यबल विकास और बुनियादी ढांचे में वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करते हुए, वंचित समुदायों को सेवाएं प्रदान करने के लिए मिलकर काम करते हैं।
- गैर सरकारी संगठन और नागरिक समाज सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील स्वास्थ्य पहलों को तैयार करने के लिए अंतरराष्ट्रीय और सरकारी संगठनों के साथ सहयोग करते हुए, क्षेत्रीय स्वास्थ्य चिंताओं को दूर करने के लिए सामुदायिक आउटरीच का संचालन करते हैं।
- **WHO, ग्लोबल फंड और गावी** जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थान संसाधन-सीमित क्षेत्रों में स्वास्थ्य पहल का समर्थन करते हैं और विशेष रूप से भारत जैसे देशों में स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों को मजबूत करने के लिए सूचना और संसाधन साझाकरण को बढ़ावा देते हैं।
- वाणिज्यिक क्षेत्र और धर्मार्थ संगठन स्वास्थ्य देखभाल की पहुंच, सामर्थ्य और प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए, विशेष रूप से डिजिटल स्वास्थ्य में नवाचार और तकनीकी प्रगति का लाभ उठाते हैं।
- अनुसंधान संस्थान और शैक्षणिक संस्थान स्वास्थ्य असमानताओं को समझने और हस्तक्षेप प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने, वैज्ञानिक अध्ययनों द्वारा समर्थित साक्ष्य-आधारित प्रथाओं और नीतियों में योगदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

इन संगठनों को टैप करें (Tap these organisations)

- **स्थानीय संगठन** सामुदायिक आवश्यकताओं की अपनी समझ के आधार पर, योजना से लेकर मूल्यांकन तक, स्वास्थ्य कार्यक्रमों के सभी चरणों में सक्रिय रूप से भाग लेकर स्वास्थ्य समानता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं।
- स्वास्थ्य समानता के लिए सफल सहयोग खुले संचार, आपसी सम्मान और साझा लक्ष्यों पर निर्भर करते हैं, जो बदलती स्वास्थ्य चिंताओं और सामुदायिक जरूरतों के अनुकूल अनुकूलन की अनुमति देते हैं।
- नीति निर्माताओं और जमीनी स्तर के संगठनों सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग, स्वास्थ्य समानता को काफी बढ़ा सकता है और उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच को सभी के लिए एक साझा वास्तविकता बनाने की दिशा में काम कर सकता है।

आयुष्मान भारत

- **प्रमुख स्वास्थ्य योजना:** आयुष्मान भारत, जिसे आधिकारिक तौर पर प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई) के रूप में जाना जाता है, भारत सरकार की प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजना है।
- **लॉन्च:** 2018 में घोषित।
- **उद्देश्य:** देश की आर्थिक रूप से कमजोर आबादी को वित्तीय सुरक्षा और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करना।

ज़रूरी भाग:

1. **आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY):**

PatrioticIAS

- प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपये तक का माध्यमिक और तृतीयक अस्पताल में भर्ती कवरेज प्रदान करता है।
- गरीब और सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले लगभग 500 मिलियन लाभार्थियों को लक्षित करता है।
- सूचीबद्ध निजी और सार्वजनिक अस्पतालों तक कैशलेस और पेपरलेस पहुंच।

2. **स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र (एचडब्ल्यूसी):**
   - समुदायों के करीब व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए 150,000 उप-स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को एचडब्ल्यूसी में अपग्रेड करने का लक्ष्य है।
   - सामान्य बीमारियों और गैर-संचारी रोगों के लिए निवारक देखभाल, जांच और उपचार पर ध्यान केंद्रित करता है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM)

- NHM 2005 में शुरू की गई भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसमें पहले के दो मिशन शामिल हैं:
  - राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम)
  - राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एनयूएचएम)
- मुख्य कार्यक्रम घटकों में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण (आरएमएनसीएच+ए)- प्रजनन-मातृ-नवजात-बाल और किशोर स्वास्थ्य, और संचारी और गैर-संचारी रोग शामिल हैं।
- NHM न्यायसंगत, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच की उपलब्धि की परिकल्पना करता है जो लोगों की जरूरतों के प्रति जवाबदेह और उत्तरदायी हो।

प्रमुख उद्देश्य:

- **स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाना:**
  - बेहतर उपकरण, मानव संसाधन और सेवाओं के साथ ग्रामीण और शहरी स्वास्थ्य सुविधाओं को उन्नत करना।
  - नए उप-केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करना।
- **मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी:**
  - प्रसवपूर्व और प्रसवोत्तर देखभाल, संस्थागत प्रसव और टीकाकरण कार्यक्रमों सहित मातृ स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार पर ध्यान दें।
  - कुपोषण और संचारी रोगों जैसी बाल स्वास्थ्य चुनौतियों का समाधान करना।
- **संचारी रोगों पर नियंत्रण:**
  - रोग निगरानी प्रणालियों को मजबूत करना।
  - टीबी, मलेरिया, एचआईवी/एड्स और अन्य संचारी रोगों के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम लागू करना।
- **सस्ती दवाओं तक पहुंच बढ़ी:**
  - सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं पर आवश्यक दवा की उपलब्धता और सामर्थ्य को बढ़ावा देना

वैश्विक निधि

- **बहुपक्षीय वित्तपोषण संगठन:** ग्लोबल फंड 2002 में स्थापित एक वैश्विक साझेदारी है जिसका उद्देश्य एचआईवी/एड्स, तपेदिक (टीबी) और मलेरिया के खिलाफ लड़ाई में तेजी लाना है।
- **फंडिंग संरचना:** यह सरकारों, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र और तीन बीमारियों से प्रभावित लोगों के सहयोग पर निर्भर करती है। संगठन संसाधनों को एकत्रित करता है और उन्हें उच्च रोग बोझ वाले निम्न और मध्यम आय वाले देशों में वितरित करता है।

Patriot IAS

- **प्रभाव-संचालित निवेश:** यह परिणामों और मापने योग्य परिणामों पर ध्यान देने के साथ देश के नेतृत्व वाले दृष्टिकोण पर जोर देता है।

मुख्य फोकस क्षेत्र:

- **एचआईवी/एड्स:** रोकथाम, परीक्षण, उपचार, देखभाल और सहायता कार्यक्रमों के लिए धन उपलब्ध कराता है।
- **क्षय रोग:** टीबी मामले का पता लगाने, निदान, उपचार और दवा प्रतिरोधी टीबी देखभाल का समर्थन करता है।
- **मलेरिया:** कीटनाशक-उपचारित मच्छरदानी, इनडोर छिड़काव, उपचार और निवारक उपचारों में निवेश करता है।
- **स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत बनाना:** मजबूत स्वास्थ्य देखभाल बुनियादी ढांचे के महत्व को स्वीकार करता है, इसलिए अपनी रणनीति के हिस्से के रूप में स्वास्थ्य प्रणालियों का समर्थन करता है।

यह काम किस प्रकार करता है:

- **संसाधन जुटाना:** ग्लोबल फंड दाता देशों, निजी क्षेत्र और फाउंडेशनों से बहु-वर्षीय प्रतिज्ञाओं के माध्यम से धन जुटाता है।
- **देश-आधारित प्रस्ताव:** जरूरतमंद देश प्रस्ताव विकसित करते हैं, जिनकी फंडिंग मंजूरी के लिए ग्लोबल फंड समीक्षा करता है।
- **अनुदान कार्यान्वयन:** जिन देशों को अनुदान दिया जाता है वे ग्लोबल फंड की तकनीकी सहायता और निगरानी के साथ कार्यक्रमों को लागू करते हैं।

गावी(Gavi), वैक्सीन एलायंस

- **लक्ष्य:** गावी 2000 में स्थापित एक वैश्विक सार्वजनिक-निजी भागीदारी है, जो दुनिया के सबसे गरीब देशों में बच्चों के लिए नए और कम उपयोग वाले टीकों तक पहुंच में सुधार के लिए समर्पित है।

गावी कैसे स्वास्थ्य पहल का समर्थन करता है

1. **वैक्सीन फंडिंग:** गावी पात्र देशों के लिए वैक्सीन की लागत पर सब्सिडी देने के लिए दाता सरकारों, परोपकारी संगठनों, निजी क्षेत्र और नवीन वित्तपोषण तंत्र से धन जुटाता है।
2. **खरीद और आपूर्ति श्रृंखला:** गावी टीकों की मांग एकत्र करता है, निर्माताओं के साथ कम कीमतों पर बातचीत करता है, और यह सुनिश्चित करने के लिए विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखलाओं का समर्थन करता है कि टीके सबसे कमजोर समुदायों तक पहुंचें।
3. **टीकाकरण प्रणाली को मजबूत बनाना:** गावी वैक्सीन वितरण के लिए स्वास्थ्य प्रणाली में सुधार के लिए देशों को अनुदान प्रदान करता है, जिसमें कोल्ड चेन उपकरण, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण और डेटा संग्रह शामिल है।
4. **वकालत और साझेदारी:** गावी टीकाकरण के महत्व की वकालत करने और स्थायी कार्यक्रमों के लिए समर्थन तैयार करने के लिए सरकारों, नागरिक समाज, WHO, यूनिसेफ और अन्य भागीदारों के साथ काम करता है।

गावी का प्रभाव:

- **बढ़ी हुई पहुंच:** गावी ने खसरा, पोलियो, डिप्थीरिया और कई अन्य बीमारियों के लिए टीकाकरण दर बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे लाखों बच्चों की मृत्यु को रोका जा सके।
- **समानता:** कमजोर स्वास्थ्य प्रणालियों वाले कम आय वाले देशों पर गावी का ध्यान यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि सबसे कमजोर बच्चों को जीवन रक्षक टीके प्राप्त हों।
- **नवाचार:** गावी वैक्सीन विकास, वितरण और वित्तपोषण मॉडल में नवाचार को बढ़ावा देता है

PolioticIAS

मुख्य अभ्यास प्रश्न: GS PAPER II: स्वास्थ्य क्षेत्र

Q6. "कल्याणकारी राज्य की नैतिक अनिवार्यता होने के अलावा, प्राथमिक स्वास्थ्य संरचना सतत विकास के लिए एक आवश्यक पूर्व शर्त है।" विश्लेषण। (150 शब्द/10 अंक) (यूपीएससी 2021)

- सामाजिक विकास की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए, विशेष रूप से वृद्धावस्था और मातृ स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में ठोस और पर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल नीतियों की आवश्यकता है। चर्चा करना। **(150 शब्द/10 अंक) (यूपीएससी 2020)**
- COVID-19 महामारी के दौरान वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने में WHO की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण करें। **(150 शब्द/10 अंक) (यूपीएससी 2020)**

- भारत में 'सभी के लिए स्वास्थ्य' हासिल करने के लिए उचित स्थानीय सामुदायिक स्तर पर स्वास्थ्य देखभाल हस्तक्षेप एक शर्त है। व्याख्या करना। (150 शब्द/10 अंक) (यूपीएससी 2018)

- सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करने में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की सीमाएँ हैं। क्या आपको लगता है कि निजी क्षेत्र इस अंतर को पाटने में मदद कर सकता है? आप अन्य कौन से व्यवहार्य विकल्प सुझाते हैं? (200 शब्द/12.5 अंक) (यूपीएससी 2015)

प्रश्न 2: भारत में स्वास्थ्य समानता के मुद्दों को संबोधित करने में आयुष्मान भारत और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) जैसी सरकारी पहलों की भूमिका का मूल्यांकन करें, उनकी ताकत और सीमाओं पर प्रकाश डालें। (250 शब्द/15 अंक)

प्रश्न 1: भारत, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी मलिन बस्तियों में सामना की जाने वाली प्रमुख स्वास्थ्य समानता चुनौतियों और हाशिए पर रहने वाले समुदायों पर उनके प्रभाव का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। (250 शब्द/15 अंक)

उत्तर दृष्टिकोण

- स्वास्थ्य समानता को परिभाषित करके या भारत की स्वास्थ्य सेवा असमानताओं पर प्रकाश डालकर परिचय
- प्रमुख स्वास्थ्य समानता चुनौतियाँ लाएँ
- हाशिए पर रहने वाले समुदायों पर प्रभाव डालें
- फिर क्रिटिकल विश्लेषण मौजूदा नीतियों का मूल्यांकन करके और संरचनात्मक मुद्दों की पहचान करके सरकारी पहल
- ऐसी नीति और कार्यक्रम डिजाइन की आवश्यकता पर जोर देते हुए निष्कर्ष निकालें जो स्पष्ट रूप से हाशिए पर रहने वाले समूहों को प्राथमिकता देती हो।

उत्तर

स्वास्थ्य समानता का तात्पर्य स्वास्थ्य देखभाल संसाधनों और सेवाओं के उचित वितरण से है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि सभी को अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करने का समान अवसर मिले। हालाँकि, भारत को विशेष

Patriot IAS

रूप से ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी मलिन बस्तियों में स्वास्थ्य समानता हासिल करने में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

भारत में प्रमुख स्वास्थ्य समानता चुनौतियाँ:

- **ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल तक सीमित पहुंच:** अपर्याप्त बुनियादी ढांचे, चिकित्सा पेशेवरों की कमी और भौगोलिक बाधाओं के कारण ग्रामीण आबादी को अक्सर स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
- **शहरी मलिन बस्तियों में स्वास्थ्य असमानताएँ:** शहरी मलिन बस्तियाँ भीड़भाड़, खराब स्वच्छता और साफ पानी तक सीमित पहुंच से पीड़ित हैं, जिससे तपेदिक जैसे संक्रामक रोगों का प्रसार बढ़ जाता है और मृत्यु दर भी अधिक हो जाती है।
- **भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अनुसार, तपेदिक जैसी संक्रामक बीमारियाँ गैर-झुग्गी बस्तियों की तुलना में मलिन बस्तियों में 1.5 गुना अधिक आम हैं।**
- **जाति और लिंग असमानताएँ:** अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जैसे हाशिये पर रहने वाले समुदाय उच्च बाल मृत्यु दर और कम टीकाकरण दर का अनुभव करते हैं। निम्न आर्थिक पृष्ठभूमि की महिलाओं को एनीमिया के उच्च प्रसार का सामना करना पड़ता है, जो स्वास्थ्य देखभाल परिणामों में जाति, लिंग और आर्थिक स्थिति के अंतर्संबंध को दर्शाता है।
- **गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) का बोझ:** एनसीडी भारत के रोग बोझ के एक महत्वपूर्ण हिस्से में योगदान करते हैं, साथ ही भविष्य के लिए पर्याप्त आर्थिक लागत का अनुमान लगाया जाता है। निवारक और उपचारात्मक सेवाओं तक सीमित पहुंच हाशिए पर रहने वाले समुदायों पर एनसीडी के प्रभाव को बढ़ा देती है।
- **स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं की कमी:** भारत को डॉक्टरों की गंभीर कमी का सामना करना पड़ रहा है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, डॉक्टर-जनसंख्या अनुपात अनुशंसित स्तर से नीचे गिर रहा है। यह कमी स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच के अंतर को और बढ़ा देती है।

हाशिए पर रहने वाले समुदायों पर प्रभाव:

- स्वास्थ्य समानता की चुनौतियाँ हाशिए पर रहने वाले समुदायों को असमान रूप से प्रभावित करती हैं, जिससे मौजूदा सामाजिक और आर्थिक असमानताएँ बढ़ जाती हैं।
- गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच की कमी गरीबी और खराब स्वास्थ्य के चक्र को कायम रखती है, जिससे सामाजिक-आर्थिक विकास में बाधा आती है।

सरकारी पहलों का आलोचनात्मक विश्लेषण:

- हालांकि आयुष्मान भारत और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) जैसी सरकारी पहलों का उद्देश्य स्वास्थ्य देखभाल संबंधी असमानताओं को दूर करना है, लेकिन संरचनात्मक मुद्दे बरकरार हैं।
- चुनौतियों में अपर्याप्त धन, क्षेत्रों में असमान कार्यान्वयन और स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारकों को संबोधित करने पर सीमित ध्यान शामिल है।

इस प्रकार , स्वास्थ्य समानता हासिल करने की दिशा में भारत की यात्रा के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार से परे हो। स्वास्थ्य संबंधी असमानताओं के मूल कारणों, जैसे गरीबी, भेदभाव और शिक्षा और स्वच्छता तक अपर्याप्त पहुंच को संबोधित करना आवश्यक है। समाज के सभी वर्गों के लिए समावेशी और न्यायसंगत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने के लिए नीति और कार्यक्रम डिजाइन में हाशिए पर रहने वाले समूहों को स्पष्ट रूप से प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

Patriot IAS

स्वच्छंद हाथी: आरबीआई के दर निर्णय पर (GS PAPER III: मुद्रास्फीति)

- आरबीआई की **मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी)** ने लगातार सातवीं बैठक में बेंचमार्क पॉलिसी रेपो रेट को 6.5% पर बनाए रखने का फैसला किया है।

- यह निर्णय लगातार खाद्य मूल्य दबावों से प्रभावित है जो मुद्रास्फीति को स्थायी आधार पर 4% के लक्ष्य तक नीचे लाने के प्रयासों में बाधा बन रहा है।
- **आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास** मुद्रास्फीति को 'कमरे में हाथी' के रूप में वर्णित किया गया है , यह देखते हुए कि अप्रैल 2022 में यह 7.8% पर पहुंच गया था, लेकिन अब इसमें नरमी के संकेत दिख रहे हैं।
- लक्ष्य **यह सुनिश्चित करना है कि मुद्रास्फीति लगातार कम रहे और अर्थव्यवस्था के लाभ के लिए लक्ष्य के अनुरूप रहे।**
- प्रयासों के बावजूद, **हेडलाइन मुद्रास्फीति, विशेष रूप से खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति**, फरवरी 2024 तक लगातार 53 महीनों तक आरबीआई के 4% लक्ष्य को पार करते हुए अप्रत्याशित रूप से उच्च बना हुआ है।
- नए वित्तीय वर्ष के लिए एमपीसी के अनुमानों से पता चलता है कि मौजूदा तिमाही में सीपीआई मुद्रास्फीति में मामूली कमी होकर औसतन 4.9% रह जाएगी, इसके बाद दूसरी तिमाही में घटकर 3.9% रह जाएगी। हालाँकि, Q3 और Q4 में इसके फिर से बढ़कर क्रमशः 4.6% और 4.5% होने की उम्मीद है।
- एमपीसी ने मार्च 2025 में समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए आर्थिक विकास में विश्वास व्यक्त करते हुए सकल घरेलू उत्पाद में 7% विस्तार का अनुमान लगाया है।
- इस दृष्टिकोण में योगदान देने वाले कारकों में सामान्य दक्षिण-पश्चिम मानसून की उम्मीदें शामिल हैं, जो कृषि गतिविधि और ग्रामीण मांग को बढ़ावा देगी, साथ ही विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में निरंतर गति प्रदान करेगी।
- आरबीआई के मार्च उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण से संकेत मिलता है कि शहरी परिवार मौजूदा स्थिति के बारे में कम निराशावादी हैं और एक वर्ष के भीतर प्रमुख मापदंडों में सुधार की आशा करते हैं।
- मौद्रिक नीति निर्माताओं का मानना है कि बढ़ती आय और गैर-जरूरी चीजों पर खर्च करने की इच्छा बढ़ने से निजी खपत मजबूत होगी, जो हाल की तिमाहियों में सुस्त रही है।
- आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास के अनुसार, मजबूत प्रत्याशित वृद्धि आरबीआई को मुद्रास्फीति को लक्षित करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए जगह प्रदान करती है।
- लगातार मुद्रास्फीति ने न केवल विवेकाधीन खर्च को सीमित कर दिया है, बल्कि आवश्यक खर्चों के लिए व्यक्तिगत ऋण में भी वृद्धि हुई है, जो मूल्य स्थिरता बहाल करने के महत्व को रेखांकित करता है।
- मुद्रास्फीति को आर्थिक विकास की गति में बाधा बनने से रोकने के लिए मूल्य स्थिरता बनाए रखना महत्वपूर्ण है।

गर्मी को मात दें: अधिक लू चलने की आईएमडी(IMD) की चेतावनी पर (GS PAPER I: प्राकृतिक घटना)

- आईएमडी ने इस गर्मी में और अधिक लू चलने की चेतावनी दी है, जो विशेष रूप से आंध्र प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र को प्रभावित करेगी।
- लू वाले दिन वे होते हैं जब तापमान **लगातार दो दिनों तक सामान्य से कम से कम 4.5 डिग्री सेल्सियस ऊपर या 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है।**
- आवर्ती **अल नीनो घटना, जो आम तौर पर वर्षा को कम करती है और तापमान बढ़ाती है, भारत में गर्म गर्मियों में योगदान करती है।**

- अल नीनो के कारण तापमान बढ़ने से आर्कटिक में पिघलने की गति तेज हो गई, उष्णकटिबंधीय हवाएं सूख गईं और बादलों का आवरण कम हो गया, जिसके परिणामस्वरूप जमीन का तापमान बढ़ गया।
- चिंताएँ पैदा होती हैं क्योंकि अप्रैल और मई में आगामी चुनावों के दौरान लाखों लोगों के मतदान केंद्रों पर कतार में खड़े होने की उम्मीद है।
- **पिछली घटनाएं, जैसे नवी मुंबई की घटना, जहां एक राजनीतिक कार्यक्रम में निर्जलीकरण के कारण 12 लोगों की मौत हो गई, हीटवेव के दौरान सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रति विचार की कमी को रेखांकित करती है।**
- भारत के चुनाव आयोग ने उच्च तापमान के बीच मतदान की तैयारी के लिए सामान्य सलाह जारी की है, लेकिन उनमें शीतलन और जलयोजन के लिए विशिष्ट उपायों का अभाव है।
- **फरवरी-मार्च या अक्टूबर-नवंबर जैसे ठंडे महीनों के दौरान चुनाव कराने के सुझावों को तार्किक चुनौतियों के कारण लगातार लागू नहीं किया जाता है।**
- बढ़ते तापमान और लू, जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य के बीच स्पष्ट संबंधों के साथ, चुनावी प्रक्रियाओं के दौरान संकट से निपटने के लिए नवीन समाधानों की आवश्यकता है।

बहुत जल्दी ख़त्म हो गया - भारत में युवा आत्महत्या का विषय (GS PAPER I: समाज)

भारत में चुप्पी और निष्क्रियता के कारण आत्महत्या से किसी भी युवा की जान नहीं जानी चाहिए

- आत्महत्या जीवन की एक दुखद हानि है जो तब घटित होती है जब व्यक्ति जानबूझकर अपना जीवन समाप्त करने का निर्णय लेता है।
- 2022 में 1.71 लाख रिपोर्ट किए गए मामलों के साथ, भारत को वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक आत्महत्याओं का दुर्भाग्यपूर्ण गौरव प्राप्त है।
- आत्महत्या **की दर प्रति 1,00,000 लोगों पर 12.4 तक पहुंच गई है।** भारत में अब तक का सबसे अधिक रिकॉर्ड किया गया।
- हालाँकि, अपर्याप्त पंजीकरण प्रणाली, चिकित्सा प्रमाणन की कमी और आत्महत्या से जुड़े कलंक जैसे मुद्दों के कारण इन आंकड़ों को कम करके आंका गया है।
- चिंताजनक बात यह है कि **भारत में सभी आत्महत्याओं में से 41% 30 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों द्वारा की जाती हैं** , जिससे आत्महत्या युवा महिलाओं की मृत्यु का प्रमुख कारण बन जाती है।
- हर आठ मिनट में एक युवा भारतीय आत्महत्या से मर जाता है , जिसका परिवारों, समाज, अर्थव्यवस्था और देश के भविष्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।
- भारत में युवाओं में आत्महत्या एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता है, जिस पर तत्काल ध्यान देने और निवारक उपायों की आवश्यकता है।

कोई एक कारक नहीं है

- आत्महत्या एक जटिल व्यवहार है जो **जैविक, मनोवैज्ञानिक, पारिवारिक और सामाजिक-सांस्कृतिक पहलुओं सहित विभिन्न कारकों से प्रभावित होता है** ।

PatriotIAS

- भारत में, सबसे अधिक सूचित जोखिम कारक मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं (54%), नकारात्मक या दर्दनाक पारिवारिक मुद्दे (36%), शैक्षणिक तनाव (23%), सामाजिक और जीवनशैली कारक (20%), हिंसा (22%), आर्थिक थे। संकट (9.1%) और संबंध कारक (9%)। युवा आत्महत्या के लिए सामान्य जोखिम कारक हैं।
- युवा लड़कियों और महिलाओं को प्रभावित करने वाले विशिष्ट सामाजिक-सांस्कृतिक कारकों में **व्यवस्थित और कम उम्र में विवाह, घरेलू हिंसा, निम्न सामाजिक स्थिति और कठोर लिंग भूमिकाएँ।**
- शैक्षणिक दबाव, माता-पिता की अपेक्षाएं और उच्च अंक प्राप्त करने पर जोर युवाओं में शैक्षणिक तनाव और परीक्षा संबंधी आत्महत्याओं में योगदान देता है।
- शराब और मादक द्रव्यों के सेवन के साथ-साथ अत्यधिक इंटरनेट और सोशल मीडिया के उपयोग से युवाओं में आत्महत्या का खतरा बढ़ जाता है।
- **आत्महत्या के मामलों की सनसनीखेज रिपोर्टिंग, विशेष रूप से मशहूर हस्तियों से जुड़ी, कमजोर व्यक्तियों के बीच नकलची व्यवहार को जन्म दे सकती है** , जो आत्मघाती व्यवहार पर मीडिया के प्रभाव को उजागर करती है।

समाधान हैं

- **एक आम धारणा है कि आत्महत्याओं को रोका नहीं जा सकता है** , अक्सर व्यक्तिगत पसंद या नियंत्रण से परे सामाजिक-आर्थिक कारकों को जिम्मेदार ठहराया जाता है।
- हालाँकि, कई युवा जो आत्महत्या के बारे में सोचते हैं उनके पास अपनी समस्याओं के वैकल्पिक समाधान की क्षमता होती है।
- **समस्या-समाधान, आवेग नियंत्रण और भावनात्मक विनियमन कौशल सिखाना** युवाओं को चुनौतियों से निपटने और उचित मदद लेने में मदद मिल सकती है।
- **मानसिक परेशानी की शीघ्र पहचान करना और युवा-अनुकूल वातावरण में देखभाल प्रदान करना** रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण है।
- संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और इंटरनेट के उपयोग में संयम सहित स्वस्थ जीवन शैली अपनाने से मानसिक स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है और आत्महत्या के जोखिम को कम किया जा सकता है।
- **घरेलू हिंसा और शराब की खपत** जैसे मुद्दों को संबोधित करके और आर्थिक सहायता प्रदान करके पारिवारिक गतिशीलता में सुधार करने से आत्महत्या को रोकने में मदद मिल सकती है।
- **शैक्षिक सुधार, जैसे वैकल्पिक मूल्यांकन पद्धतियाँ और अवसर** व्यक्तिगत क्षमता की खोज के लिए आवश्यक हैं।
- **आत्महत्या की रोकथाम के लिए जाति, धर्म और कामुकता जैसे कारकों के आधार पर कलंक और भेदभाव को कम करने के लिए सामाजिक परिवर्तन आवश्यक हैं।**
- **प्रभावी आत्महत्या रोकथाम प्रयासों के लिए राजनीतिक प्रतिबद्धता, सभी क्षेत्रों में सहयोग और सामुदायिक भागीदारी महत्वपूर्ण है।**

एक ऐसी रणनीति जिसके लिए अधिक दृश्यता की आवश्यकता है

- स्वास्थ्य मंत्रालय ने **भारत के लिए राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति विकसित करने के लिए नवंबर 2019 में एक टास्क फोर्स का गठन किया।**

PatriotIAS

- अंतिम रणनीति 21 नवंबर, 2022 को शुरू की गई थी, जिसका लक्ष्य 2030 तक आत्महत्या की दर को 10% तक कम करना था।
- **स्वास्थ्य, शिक्षा, सूचना और प्रसारण और समाज कल्याण सहित** विभिन्न मंत्रालयों के बीच सहयोग को रणनीति की सफलता के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है।
- रणनीति मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और मादक द्रव्यों के सेवन और व्यवहार संबंधी व्यसनों को कम करने **के लिए शैक्षणिक संस्थानों और युवा संगठनों का लाभ उठाने पर जोर देती है।**
- इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के साधन के रूप में स्कूल स्वास्थ्य राजदूतों और युवा क्लबों को प्रस्तावित किया गया है।
- तत्काल प्राथमिकता पूरे भारत में सभी राज्यों और हितधारकों तक रणनीति का प्रसार करना है।
- **पर्याप्त बजट आवंटन** राज्य, जिला और सामुदायिक स्तर पर रणनीतियों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक हैं।

प्रश्न 1: आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) मुख्य रूप से प्रदान करती है: (ए) उन्नत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों पर प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएँ (बी) माध्यमिक और तृतीयक अस्पताल में भर्ती के लिए वित्तीय सुरक्षा (सी) नए अस्पतालों के निर्माण के लिए बुनियादी ढांचे का समर्थन (डी) सरकारी फार्मेसियों में सब्सिडी वाली दवाएं	उत्तर: (बी) माध्यमिक और तृतीयक अस्पताल में भर्ती के लिए वित्तीय सुरक्षा स्पष्टीकरण: PMJAY का मुख्य घटक अधिक उन्नत चिकित्सा देखभाल आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए अस्पताल में भर्ती लागत के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रदान करता है।
प्रश्न 2: निम्नलिखित में से कौन सा समूह आयुष्मान भारत योजना का प्राथमिक लक्षित लाभार्थी है? (ए) सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी (बी) आर्थिक रूप से कमजोर परिवार (सी) शहरी मध्यमवर्गीय परिवार (डी) ईएसआई द्वारा कवर किए गए औद्योगिक श्रमिक	उत्तर: (बी) आर्थिक रूप से कमजोर परिवार स्पष्टीकरण: आयुष्मान भारत SECC (सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना) डेटा और अन्य मानदंडों का उपयोग करके पहचाने गए सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के लोगों को लक्षित करता है।
प्रश्न 3: आयुष्मान भारत - पीएमजेएवाई के तहत, प्रति पात्र परिवार प्रति वर्ष वित्तीय कवरेज है: (ए) 1 लाख रूपये (बी) INR 3 लाख (सी) INR 5 लाख (डी) 10 लाख रुपये	उत्तर: (सी) 5 लाख रुपये स्पष्टीकरण: यह योजना प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करती है।
प्रश्न 4: आयुष्मान भारत - पीएमजेएवाई के तहत सेवाएं कैसे प्रदान की जाती हैं इसकी एक प्रमुख विशेषता की पहचान करें। (ए) केवल सरकारी अस्पतालों का अनिवार्य उपयोग (बी) बीमारी के प्रकार के आधार पर प्रतिबंधित पात्रता (सी) सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों दोनों के लिए कवरेज (डी) सभी चिकित्सा प्रक्रियाओं के लिए पूर्व-अनुमोदन आवश्यक है	उत्तर: (सी) सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों दोनों के लिए कवरेज स्पष्टीकरण: PMJAY लाभार्थियों को सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के नेटवर्क से कवर उपचार प्राप्त करने की अनुमति देकर पहुंच का विस्तार करता है।

Patriot IAS

प्रश्न 5: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) निम्नलिखित में से किस पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य क्षेत्र की योजनाओं को एकीकृत करता है? (ए) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एनयूएचएम) (बी) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (एनएसीपी) और संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम (आरएनटीसीपी) (सी) प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) और आयुष्मान भारत (डी) राष्ट्रीय आयुष मिशन और राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम	उत्तर: (ए) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एनयूएचएम) स्पष्टीकरण: भारत में स्वास्थ्य देखभाल के लिए एक समग्र दृष्टिकोण बनाने के लिए एनआरएचएम और एनयूएचएम को विलय करके NHM का गठन किया गया था।
प्रश्न 6: निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) का प्रमुख उद्देश्य है? (ए) पोलियो और खसरा का उन्मूलन (बी) सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करना (सी) मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना (डी) प्रत्येक जिले में नए तृतीयक देखभाल अस्पतालों का निर्माण	उत्तर: (सी) मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना स्पष्टीकरण: जबकि NHM का दायरा व्यापक है, मुख्य फोकस मातृ, नवजात और बाल स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार करना है।
प्रश्न 7: स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों (एचडब्ल्यूसी) की स्थापना इसका एक महत्वपूर्ण घटक है: (ए) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) (बी) आयुष्मान भारत - पीएमजेवाई (सी) राष्ट्रीय पोषण मिशन (पोषण अभियान) (डी) स्वच्छ भारत मिशन	उत्तर: (ए) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) स्पष्टीकरण: एचडब्ल्यूसी, जो मौजूदा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को उन्नत करते हैं, NHM का एक प्रमुख घटक हैं, जिसका लक्ष्य प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को समुदायों के करीब लाना है।
प्रश्न 8: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. यह पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। 2. राज्य और केंद्रशासित प्रदेश इसके कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं? (ए) केवल 1 (बी) केवल 2 (सी) 1 और 2 दोनों (डी) न तो 1 और न ही 2	उत्तर: (बी) केवल 2 स्पष्टीकरण: NHM एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जहां केंद्र सरकार वित्तीय और तकनीकी दोनों सहायता प्रदान करती है, लेकिन राज्यों की उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप स्वास्थ्य कार्यक्रमों की योजना बनाने और उन्हें लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
प्रश्न 9: भारत में लू के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: यदि अधिकतम तापमान सामान्य तापमान से कम से कम 4.5 डिग्री सेल्सियस अधिक हो तो हीटवेव घोषित की जाती है। अधिकतम तापमान 47°C से अधिक होने पर भीषण लू की घोषणा की जाती है। उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं? (ए) केवल 1 (बी) केवल 2	उत्तर: (सी) 1 और 2 दोनों स्पष्टीकरण: भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) हीटवेव घोषणाओं के लिए इन मानदंडों का उपयोग करता है। हीटवेव असामान्य रूप से गर्म मौसम की अवधि है जो सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करती है।

PatriotiCIAS

(सी) 1 और 2 दोनों (डी) न तो 1 और न ही 2	
प्रश्न 10: निम्नलिखित में से किस स्थिति का उपयोग हीटवेव दिवस को परिभाषित करने के लिए किया जा सकता है? (ए) जब मैदानी इलाकों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक रहता है (बी) जब अधिकतम तापमान सामान्य से 4.5 डिग्री सेल्सियस से 6.4 डिग्री सेल्सियस तक प्रस्थान करता है (सी) जब वास्तविक अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस या अधिक रहता है (D। उपरोक्त सभी	उत्तर: (डी) उपरोक्त सभी स्पष्टीकरण: आईएमडी हीटवेव दिवस को परिभाषित करने के लिए कारकों के संयोजन का उपयोग करता है। ये कारक किसी क्षेत्र के सामान्य तापमान, उन सामान्य से विचलन और पूर्ण तापमान सीमा को ध्यान में रखते हैं।
प्रश्न 11: हीटवेव अक्सर संबंधित होती हैं: (ए) उच्च आर्द्रता का स्तर (बी) स्थिर वायु परिसंचरण (सी) प्रतिचक्रवातों की उपस्थिति (D। उपरोक्त सभी	उत्तर: (डी) उपरोक्त सभी स्पष्टीकरण: हीटवेव आमतौर पर तब होती है जब उच्च दबाव प्रणाली (एंटीसाइक्लोन) एक क्षेत्र पर स्थिर हो जाती है। इससे हवा डूबने लगती है, जो गर्म होकर सूख जाती है, जिसके परिणामस्वरूप उच्च तापमान और आर्द्रता होती है। स्थिर वायु परिसंचरण ठंडी हवा को अंदर आने से रोकता है।

PatrioticIAS